निजी स्कूलों से जूझते अभिभावक मंच के लिये करने को बहुत कुछ है

फ़रीदाबाद (म.मो.) आम आदमी के बच्चों को मुफ़्त में शिक्षा देने वाली सरकारी शिक्षा व्यवस्था का शासक वर्गों द्वारा सत्यानाश कर दिये जाने के चलते निजी एवं मंहगे स्कूलों की भरमार हो गयी है। मासिक 2000 से 6000 तक फ़ीस वसूलने वाले इन सकूलों में वे बच्चे तो झांक भी नहीं सकते जिनके परिवार की मासिक आय मात्र 6000 से 10000 रुपये है। जब चाहें जितनी चाहें फ़ीस बढा ले, जिसका चाहें दाखला रोक लें, हर तरह की मनमानी करने को स्वतन्त्र इन स्कूलों पर जब सरकार अपने ही नियम कानून लागू करने में कोताही बरतने लगी तो राज्य स्तर पर 'हरियाणा अभिभावक एकता मंच' का गठन किया गया था। अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में मंच ने कई उतार चढाव-देखे। मंच को बेशक अभी कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली, लेकिन फ़िर भी इन स्कूलों की नकेल कसने में मंच कई मामलों में कामयाब रहा है।

मंच के संस्थापक अध्यक्ष एवं जाने-माने वकील औम प्रकाश शर्मा ने एक अनौपचारिक बाचचीत में इस संवाददाता को बताया कि 60-70 के दशक में जब वे खुद पढा करते थे तो इन निजी स्कूलों का कहीं नामो-निशान भी नहीं था। हां कहीं दूर दराज के क्षेत्रों में दून स्कूल सनावर स्कूल आदि के नाम जरूर सुना करते थे जो बहुत ही हाई-फ़ाई हुआ करते थे। लेकिन इन हाई-फ़ाई स्कूलों का देश की मुख्य धारा से कोई सम्बन्ध नहीं होता था। इनमें पढने वाले पढ लिख कर क्या करते थे, कहां जाते थे, कोई ध्यान नहीं देता था।

उस समय के सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की शिक्षण व्यवस्था इतनी मजबूत व सस्ती थी कि हरेक आम व खास अपने बच्चों को इन्हीं स्कूलों में पढाता था। और इन्हीं स्कूलों से पढे बच्चे डॉक्टर, इन्जीनियर, प्रोफ़ेसर, वकील, जज और वैज्ञानिक बनते थे। देश की तमाम प्रशासनिक सेवाओं में भी इन्हीं बच्चों का बोलबाला रहता था।

लेकिन जनविरोधी शासक वर्गों को यह नहीं सुहा रहा था कि हर आम आदमी के बच्चे पढ लिख कर उच्च पदों तक पहुंच जायें। इसके साथ-साथ राजनीतिको द्वारा सरकारी मशीनरी में बढाये गये भ्रष्टाचार व निकम्मेपन के चलते तमाम सरकारी शिक्षण व्यवस्था का सत्यानाश कर दिया गया। जिन सरकारी स्कूलों में पहले तमाम अफ़सरों के बच्चे पढा करते थे उन्हीं स्कूलों में अब उस स्कूल का चपरासी भी अपने बच्चों को पढाना पसंद नहीं करता। इन स्कूलों के पास न तो अब ढंग की इमारत बची है न कोई साजो-सामान। पीने के पानी व शौचालय तक की व्यवस्था नहीं रह गयी है। पढाने वाले स्टाफ़ की बात करें तो राज्य भर में 30000 अध्यापकों के पद खाली पड़े हैं।

प्राइवेट स्कूलों को दी जाने वाली सरकारी सहायता में भी सरकार ने भारी कटौती व दखलंदाज़ी करनी शुरू कर दी। इसके चलते वे सकूल भी धीरे-धीरें बन्द होने लगे अथवा अपना चरित्र बदलने लगे। सरकारी निर्भरता से मुक्त होकर इन स्कूलों ने अपने संसाधनों के बूते स्कूल चलाने के लिये शिक्षा का पूरा व्यापारीकरण कर दिया। सरकारी कानूनों को ध्यान में रखते हुए केवल दिखावे के लिये इनके ऊपर 'चेरिटेबल' का फट्टा लगा दिया गया, बाकी सारे काम मुनाफ़ाखोरी को ध्यान में रख कर किये जाने लगे। मुनाफ़ाखोरी करें भी क्यों न जब ये लोग सरकार से नीलामी में स्कूल के लिये प्लॉट खरीदते हैं, व्यापारिक दरों पर बिजली बिलों का भुगतान करते हैं, स्कूल को चालू करने के लिये तमाम सरकारी दफ़्तरों के चक्कर लगा-लगाकर हर कदम पर रिश्वत देकर काम कराते हैं तो मुनाफ़ा क्यों नहीं लेंगे? इतना ही नहीं तमाम राजनीतिक दलों को मोटा चंदा व उनकी रैलियों के लिये बसें व अन्य संसाधन जुटाना भी इनके जिम्मे रहता है। राजनेता व अफ़सरान जहां एक ओर सरकारी स्कूलों में झांकना भी पसंद नहीं करते वहीं दूसरी ओर निजी स्कूलों में आये दिन होने वाले खेल-तमाशों में झूमते मिलेंगे।

दसियों बरस से लड़ रहा अभिभावक मंच जब सरकार से कोई राहत पा लेता है तो हाई कोर्ट उस पर रोक लगा देती है और जब हाई कोर्ट कुछ राहत की बात करती है तो सरकार उसे अनसुना कर देती है। मंच लगातार इन दोनों के बीच कलाबाज़ियां खाता आ रहा है। वास्तव में ये दोनों संस्थान शासक वर्ग के ही अंग है और दोनों पूरे तालमेल के साथ जनता की तरह मंच को भी घुम्मन-घेरी में घुमा रहे हैं। कुल मिला कर न तो सरकार की ही नीयत साफ़ है और न इसके द्वारा बनाई गयी न्यायपालिका की। वरना, यदि नीयत साफ़ होती तो यह सारा मामला 10 वर्ष तो क्या 10 घंटे का भी नहीं है।

पूछे जाने पर शर्मा जी ने बताया कि फ़िलहाल तो वे निजी स्कूलों से सम्बन्धित अभिभावकों की ही लड़ाई लड़ रहे हैंऔर केवल निजी स्कूल ही उनके निशाने पर हैं। बेशक वे इस बात पर सहमत दिखे कि यदि सरकारी स्कूलों की व्यवस्था ठीक हो जाये ता निजी स्कूलों में जाने की जरूरत ही न पड़े। लेकिन इसके लिये अभी किसी आन्दोलन की रूपरेखा उनके पास नहीं है।

विदित है कि 2 वर्ष पुराने आंकड़ों के अनुसार हरियाणा सरकार स्कूली शिक्षा पर 7400 करोड़ वार्षिक खर्च करती है। इनमें पढने वाले बच्चों की (सरकारी) संख्या 27 लाख है जबकि वास्तविक संख्या किसी भी तरह 22 लाख से अधिक नहीं हो सकती। क्योंकि सरकारी आंकड़े उन स्कूल मास्टरों के हाजिरी रजिस्टरों से लिये गये हैं जो अपनी तैनाती बनाये रखने के लिये फ़र्जी नाम दर्ज कर लेते हैं। यदि सरकारी आंकड़ों को भी सही मान लें तो प्रत्येक बच्चे पर सरकार 2200 रुपये खर्च कर रही है। इतने खर्च के बावजूद स्कूलों की जो दुर्दशा है वह स्वत: सिद्ध करती है कि उक्त 7400 करोड़ की राशी में कोई बड़ी सेंध जरूर लगी हुई है।

एक अति महत्वपूर्ण सवाल समझने वाला यह है कि जब इसी राज्य में केन्द्रीय स्कूल और पड़ोंसी राज्य दिल्ली में सरकारी स्कूल बेहतर शिक्षा प्रदान कर सकते हैं तो हरियाणा सरकार को क्या मौत पड़ रही है अपने स्कूलों को सही ढंग से चलाने में? दरअसल सत्तारूढ राजनेताओं ने सारी व्यवस्था को भ्रष्टाचार व भाई-भतीजावाद के जहर से प्रदूषित कर दिया है। सरकारी नौकरी का आधार योग्यता न रहकर भाई-भतीजावाद व रिश्वतखोरी रह गया है। इसी के फ़लस्वरूप न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि हर सरकारी महकमे का बंटाधार हुआ पड़ा है।

अभिभावक मंच यदि निजी स्कूलों के साथ-साथ सरकारी शिक्षा व्यवस्था को चुस्त-दुरूस्त कराने के लिये भी संघर्ष करे तो अपेक्षाकृत जल्दी और बेहतर परिणाम निकल सकते हैं।

सत्या इन्जीनियरिंग कॉलेज :

मालिकों की गुंडागर्दी : प्रोफ़ेसरों को दौड़ा-दौडा कर पीटा

पलवल (म.मो.) करीब 15 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित इस कॉलेज में 1200 छात्र इन्जीनियरिंग की विभिन्न शाखाओं में पढने के नाम पर भर्ती हैं। उन्हें पढाने के लिये कुल 120 प्रोफ़ेसरों को रखा गया है। अन्य स्टाफ़ अलग से। दिनांक 1 फ़रवरी 2014 को कुछ प्रोफ़ेसर अपनी मांगों को लेकर मालिकों से बात-चीत करने बैठे तो उनमें से एक जो बड़ा हिस्सेदार है हमीदातुल्ला भट्ट कुछ ज्यादा ही बद्तमीज़ी पर उतर आया। मां बहन की गालियां तक बकने लगा तो एक प्रोफ़ेसर विरोधस्वरूप अकड़ गया। हमीदातुल्ला को यह बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने टेबल पर रखा शीशा उठा कर उस प्रोफ़ेसर पर दे मारा जवाब में प्रोफ़ेसर ने भी उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। दरअसल हमीदातुल्ला को यह पता नहीं था कि वह प्रोफ़ेसर पड़ोस के ही किसी गांव का जाट था, जबकि अधिकांश स्टाफ़ दिल्ली, फ़रीदाबाद तथा दूर दराज के इलाकों से आता था। इसके बाद हमीदातुल्ला ने सिक्यूरिटी के नाम पर रखे भाड़े के गुंडे, जिन्हें आजकल बाऊंसर कहा जाता है, बुला लिये और प्रोफ़ेसरों पर हमला करा दिया। गुंडों को अपने पर भारी पड़ते देख प्रोफ़ेसर वहां से भाग खड़े हुए। मामला थाना सदर पलवल तक पहुंचा तो पुलिस ने अपनी चालू प्रणाली के तहत 'राज़ीनामा' करा दिया। इस राज़ीनामे के अनुसार मालिकान को प्रोफ़ेसरों का पिछला बकाया तमाम बेतन तथा कॉलेज छोड़ने का उचित प्रमाणपत्र मार्च 2014 तक देना था। लेकिन मार्च के बाद अप्रैल भी बीत गया परन्तु मालिकान ने प्रोफ़ेसरों का बकाया वेतन अदा नहीं किया।

उधर प्रोफ़ेसरों द्वारा सामूहिक रूप से इस्तीफ़ा देने के बाद मालिकान ने अपने यहां अन्तिम वर्ष में पढ रहे बी टेक के छात्रों को प्रोफ़ेसरों की जगह छात्रों को पढाने पर लगा दिया। विदित है कि यह ए.आई.सी.टी.ई. (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद) के नियमों की घोर अवहेलना है। किसी भी कॉलेज को मान्यता प्रदान करने से पहले ए.आई.सी.टी.ई. बाकायदा कॉलेज में पहुंच कर इस बात की पुष्टि करती है कि तमाम प्रोफ़ेसर कम से कम एम टेक यानी इन्जीनियरिंग की स्नातकोत्तर डिग्री धारक हैं। परन्तु हकीकत यह है कि एक बार पुष्टि कराने के लिये तो सही डिग्रीधारकों को ए आई सी टी ई के सामने पेश कर दिया जाता है और बाद में तमाम अर्जी-फ़र्जी लोगों को पढाने के काम पर लगा दिया जाता है। ऐसा भी नहीं है कि ए आई सी टी ई को इसका पता नहीं, उन्हें खूब पता है जिसके बदले वह कॉलेज वालों से अच्छी खासी 'भेंट' नियमित रूप से वसूलते हैं। हमीदातुल्ला के बारे में प्रोफ़ेसरों का कहना है कि वह एक बिगड़ा हुआ पुराना नौकरशाह है। वह किसी जमाने में उर्दु भाषा को बढावा देनेवाले राष्ट्रीय संस्थान का निदेशक हुआ करता था। वहां इसके द्वारा किये गये घोटालों के फलस्वरूप सी बी आई ने सन् 2005 में एक मुकदमा दर्ज करके गिरफ़्तार किया था। उसी लूट के पैसे के बल पर अब वह कॉलेज के माध्यम से अपनी लूट व गुंडागर्दी की गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। पलवल के आस-पास इस तरह के 10 इन्जीनियरिंग कॉलेज हैं। लगभग सभी में बी एड व एम बी ए के कोर्स भी हैं। कुछ कॉलेजों ने तो नई शिक्षा नीति के तहत अपने आप को विश्व-विद्यालय भी घोषित कर रखा है। वि.वि.घोषित करने का लाभ यह है के स्वयं सिलेबस बनाना परीक्षा लेना व मुल्यांकन करना। कोई बाहरी नियन्त्रण न होने के चलते ये लोग किसी को भी कोई डिग्री देने में स्वतंत्र होते हैं। इस काम के लिये न पढने की जरूरत और न ही पढाने की जरूरत होती। पढने-पढाने की जरूरत तो अब बाकी के कॉलेजों में भी नहीं रह गयी है। उनमें भी पूरा ज़ोर नकल पर ही रहता है। नकल का भी बड़ा अजब खेल है। कॉलेज मालिकान स्टाफ़ को तो कहते हैं कि किसी को नकल मत करने दो और छात्रों के कहते हैं कि नकल करो। कुल मिलाकर हालात अब ये बन गये हैं कि सटाफ़ अब छात्रों से टकराने व पिटने की बजाय चुपचाप अपनी 'ड्यूटी' पूरी करते हैं। शिक्षा के जिस हब का राग मुख्यमंत्री हुड्डा अलापते नहीं थकते, यह उसी हब की एक छोटी सी झलक है। पूंजी निवेश करके लोग इन्जीनियरिंग कॉलेज खोल देते हैं उनमें छात्र रूपी ग्राहकों को लाने के लिये जगह-जगह ये लोग अपने मार्केटिंग एजेंट बैठा कर रखते हैं। छात्रों को झूठे-सच्चे लारे-लप्पे देकर दाखला दे देते हैं। इस तरह के छात्र जैसे-तैसे डिग्री ले भी लेते हैं तो उसके बूते उन्हें जब कोई काम नहीं मिलता तो वे निराश होते हैं। इन हालात को देखकर अब इन कॉलेजों में छात्रों ने आना बहुत कम कर दिया है। इसके चलते अब कई कॉलेज बन्द होने के कगार पर हैं।

सीपी का फ्लैग मार्च : किसे डरा रहे हो-बदमाश को या शरीफ को!

पुलिस पर से विश्वास खो चुकी जनता की आंखों में धूल झोंकने एवं विश्वास बाहाली के लिए पुलिस आयुक्त अरशिन्दर चावला की नौंटकी। कौन नहीं जानता थाने चौकियों में पीड़ित शिकायतकर्ता हाथ जोड़े खड़ा रहता है और बदमाश कुर्सी पर थानेदार की बगल में बैठकर चाय की चुस्कियां लेता है।